

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 अंक - 168 जौनपुर, गुरुवार, 14 मार्च 2024 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज - 4 मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

34 एरुव एमके-3 हेलीकाप्टर की खरीद के लिए एचएएल से की 8073 करोड़ रुपये की डील

नई दिल्ली, एप्रैल 14। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उन्नत हल्के हेलीकाप्टर (एचएएल) के साथ 8073 करोड़ रुपये के दो संयुक्त अनुबंध किए हैं। इस अनुबंध के तहत भारतीय सेना और तटरक्षक बल के लिए 34 एरुव एमके-3 हेलीकाप्टर और अन्य उपकरणों का अधिग्रहण किया जाएगा। इस समझौते के तहत खरीदे जाने वाले हेलीकाप्टरों में सेना को 25 और तटरक्षक बल को नौ हेलीकाप्टर मिलेंगे। सुखा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने पिछले सप्ताह इन दो खरीद परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने कहा कि 34 एरुव एमके-3 हेलीकाप्टर सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन साबित कर चुका है। यह जल और थल दोनों के लिए उपयोगी है। एरुव एमके-3 का आइसीजी संस्करण समुद्री निगरानी, बचाव और सैनिकों के परिवहन के लिए भी डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस हेलीकाप्टर ने समुद्र और जमीन पर प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता साबित की है। इसने कहा कि यह परियोजना अपनी अवधि के दौरान अनुमानित 190 लाख घंटे का रोजगार पैदा करेगी। इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल होगी और 70 स्थानीय विक्रेता स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में शामिल होंगे।

वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लिए कार्रवाई-योग्य विचारों पर हित धारकों के साथ चर्चा की

नई दिल्ली, एप्रैल 14। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का दृष्टिकोण साकार करने के लिए विचार-विमर्श और कार्रवाई-योग्य विचारों की पहचान को मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बातचीत की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि इस संवाद में शामिल प्रतिभागियों में विभिन्न उद्योगों, स्टार्टअप, उपरते क्षेत्रों, वित्तीय-प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और शोध संस्थान के विशेषज्ञ शामिल थे। बातचीत के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन भी मौजूद थे। मंत्रालय ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "इस बातचीत का उद्देश्य भारत की क्षमता को उजागर करने के लिए एक गहरी, सहयोगात्मक बातचीत को बढ़ावा देना और भारत के विकास पथ को तेज करने के लिए सुझाव मांगना है। यह चर्चा बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने, जीवन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, समावेशी विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने और हरित एवं टिकाऊ विकास पर केंद्रित रही।"

आर्थिक प्रगति के साथ ही युवाओं को मिल रहा रोजगार - मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, संवाददाता। चीन के उत्पादों को हमने अपने मार्केट से बहुत दूर कर दिया है। यही हमारे एमएसएमई यूनित्स की ताकत का परिणाम है। इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या हो सकता है, अगर हमारे घर का उत्पाद मार्केट में छा रहा है तो हमें भी उसे प्रोत्साहित करना होगा, प्रेरित करके प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा। ये कितनी खुशी की बात है कि हमारा उत्पाद मार्केट में छा रहा है और दुश्मन देश का उत्पाद मार्केट से दूर होता जा रहा है। आज दीपावली, विजयदशमी, ईद और क्रिसमस पर यूपी के उत्पाद ही मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। हमारा उत्पाद अच्छा तो होता ही है, साथ ही हमारे उद्यमियों और कारीगरों को भी लगता है कि उनका भविष्य उज्वल है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।

रु30,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण इस दौरान उनहोंने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 30,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण किया। साथ ही उन्नाव में स्वीकृत प्लेज पार्क के विकासकर्ताओं को सीएम योगी ने चेक वितरित किया। वहीं उन्होंने औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों के आवंटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सीएम योगी ने इस अवसर पर ओडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूलकिट वितरित किया। मार्केट की संपूर्ण मैपिंग कराए विभाग अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई विभाग को मार्केट की संपूर्ण मैपिंग कराते हुए डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देना होगा। इससे



अंतर्गत टूलकिट वितरित किया। मार्केट की संपूर्ण मैपिंग कराए विभाग अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई विभाग को मार्केट की संपूर्ण मैपिंग कराते हुए डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देना होगा। इससे

उद्यम से जुड़े उद्यमियों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। आर्थिक प्रगति के साथ ही युवाओं को मिल रहा रोजगार मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन के पहले एमएसएमई विभाग की ओर से लोन वितरण के विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं। सीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष वितरित की गई राशि गत वर्ष की तुलना में दोगुना और बीते सात साल की अपेक्षा 10 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह प्रगति यूपी के आर्थिक उन्नयन को तो प्रदर्शित करता ही है साथ ही युवाओं को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। सीएम योगी ने बताया कि प्लेज पार्क से प्रदेश के 10

जनपद जुड़ चुके हैं। उन्नाव में बन रहे प्रदेश के 11वें प्लेज पार्क के लिए आज चेक वितरित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई विभाग पिछले सात साल में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के उद्यमियों के लिए नई आशा की किरण बनकर उभरा है। अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में तेजी से आगे बढ़ा है। अनलिमिटेड पोर्टेशियल वाले राज्य को बीमारू बनाकर रखा गया मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इसे लेकर बनी पुरानी धरणा

को हमने अपने सामर्थ्य से बदला है। आज हमारा हर सेक्टर सभी को उत्तर दे रहा है। यूपी पहले भी अनलिमिटेड पोर्टेशियल वाला राज्य था, मगर कुछ लोगों ने इसे बीमारू बना रखा था। हमने इसे राष्ट्रनिर्माण के अभियान के साथ जोड़कर युवाओं और उद्यमियों के डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर किया है। आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। यूपी देश का अकेला राज्य है जहां युवा उद्यमियों को बिना ब्याज के पांच लाख का ऋण देने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनित्स में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द सभी 96 लाख को रजिस्टर्ड कराना है।

लोक सभा चुनाव से पहले सीए लागू करना भाजपा की 'वोट बैंक की गंदी राजनीति' - सीएम केजरीवाल

नई दिल्ली, एप्रैल 14। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जिनके पास दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस कानून के जरिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के द्वार खोल दिए हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, "पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। भाजपा हमारे लोगों का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गरीब प्रवासियों को यहां नौकरी और घर देकर बसाने में खर्च करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में भाजपा को फायदा होगा क्योंकि पड़ोसी देशों से भारत में बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उसके वोट बैंक बन जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू करना भाजपा की वोट बैंक की गंदी राजनीति है। उन्होंने कहा कि देश सीए को निरस्त करने की मांग करता है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कानून रद्द नहीं किया गया तो वे भाजपा के खिलाफ वोट करें। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जिनके पास दस्तावेज नहीं है।



से आए गरीब प्रवासियों को यहां नौकरी और घर देकर बसाने में खर्च करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में भाजपा को फायदा होगा क्योंकि पड़ोसी देशों से भारत में बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उसके वोट बैंक बन जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू करना भाजपा की वोट बैंक की गंदी राजनीति है। उन्होंने कहा कि देश सीए को निरस्त करने की मांग करता है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कानून रद्द नहीं किया गया तो वे भाजपा के खिलाफ वोट करें। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जिनके पास दस्तावेज नहीं है।

संयुक्त या अनुबंधित किया जा सकता है, जिसमें प्लात्पाद, प्लाशोर्वाद, शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत निकाह पवित्र मिलन और आनंद कारज साथ ही विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और आर्य विवाह मान्यकरण अधिनियम, 1937 के तहत, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। 9 सदस्यीय कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया प्रावधानों के आसान कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं, सक्षम स्तर के अधिकारियों के पदनाम से संबंधित नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा वंचित वर्ग को मिला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा एससी, एसटी और ओबीसी जैसे वंचित वर्गों के लोगों को मिला है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम-सूरज (प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधुनिकीकरण) राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत के मौके पर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द और जनजातीय समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के चयन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के लोगों को शीर्ष पदों तक पहुंचाने के लिए भाजपा के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पूछा कि कोई कैसे कह सकता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। जबकि मेरे पास आप जैसे भाई और बहन हैं?

कार्यक्रम में शामिल लोगों में वंचित समूहों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शौचालय और रसोई गैस जैसे उनकी सरकार की योजनाओं से समाज के वंचित स्वच्छता श्रमिकों सहित देशभर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। इस पहल का उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। मोदी ने कहा, पिछली

लाभार्थियों के खातों में 720 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए, लेकिन यह मोदी की सरकार है, गरीबों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है। इस दौरान उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि मुद्रा योजना के तहत एससी, एसटी व ओबीसी समेत गरीब लोगों को लगभग 30 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा, जब वंचितों को वरीयता देने की भावना हो, तो कैसे काम होता है, वह इस आयोजन में दिखाई दे रहा है।

सरकार में लाखों-करोड़ रुपये के घोटाले किए गए। हमारी सरकार ये पैसा दलितों व वंचितों के कल्याण और देश के निर्माण के लिए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक वंचित वर्ग से जुड़े एक लाख



तबके को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। गरीबों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी हैं। पीएम-सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और

यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी

नई दिल्ली, एप्रैल 14। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। यह एक महीने से अधिक समय के बाद आया जब विधेयक 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानून स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यह कानून बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया शुरू करता है। यह संहिता सभी धर्मों की महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करती है। यूसीसी कानून के अनुसार, सभी समुदायों में शादी की उम्र महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के तलाक की कोई याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवाह के लिए समारोहों पर प्रकाश डालते हुए, यूसीसी कानून में कहा



लिए 21 वर्ष होगी। सभी धर्मों में विवाह पंजीकरण अनिवार्य है और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य होंगे। शादी के एक साल बाद

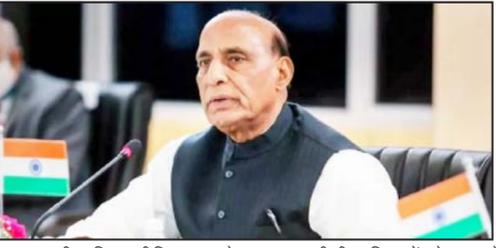
संयुक्त या अनुबंधित किया जा सकता है, जिसमें प्लात्पाद, प्लाशोर्वाद, शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत निकाह पवित्र मिलन और आनंद कारज साथ ही विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और आर्य विवाह मान्यकरण अधिनियम, 1937 के तहत, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। 9 सदस्यीय कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया प्रावधानों के आसान कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं, सक्षम स्तर के अधिकारियों के पदनाम से संबंधित नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

एनएससी में और तीन लाख कैंडेट किए जाएंगे शामिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तार प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एप्रैल 14। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैंडेट राजन (एनसीसी) के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एनसीसी में तीन लाख कैंडेट और शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एनसीसी के विस्तार से देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में इसके लिए बढ़ती मांग पूरी होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, एनसीसी में साल 1948 में केवल 20 हजार कैंडेट थे। रक्षा मंत्री द्वारा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद एनसीसी में अब 20 लाख कैंडेट की स्वीकृत संख्या होगी। इसके यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवाओं का संगठन कहलाएगा। चार नए समूह मुख्यालय की होगी स्थापना

एनसीसी की विस्तार योजना के तहत चार नए समूह मुख्यालय की स्थापना की जाएगी और दो नई एनसीसी इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि एनसीसी में तीन लाख कैंडेट के शामिल होने से सभी राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों में समान अनुपात में कैंडेट होंगे और इच्छुक संस्थानों का इंतजार खत्म होगा। इस विस्तार योजना में पूर्व सैनिकों को उनके कौशल और लंबे अनुभव के आधार पर एनसीसी प्रशिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि एनसीसी का लक्ष्य है कि वह ऐसा वातावरण तैयार कर सके, जहां युवा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने में समर्थ हों।



कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि एनसीसी में तीन लाख कैंडेट के शामिल होने से सभी राज्यों और

बंगाल में डिंटेशन कैंप की इजाजत नहीं देंगे - सीएम ममता

कोलकाता, एप्रैल 14। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नव अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर ताजा हमला करते हुए कहा कि वह असम



की तरह बंगाल में भी डिंटेशन कैंप नहीं चाहतीं। तुण्मूल कांग्रेस ने कहा कि सीएए हम आरसीसी से संबंधित है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम असम की तरह डिंटेशन

कैंप नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा काम है जनता से कहना है। भाजपा का काम है जुमलेबाजी है। उन्होंने (बीजेपी) ने कहा कि हमें 400

तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों को मिलेगा नया कार्यालय भवन

नई दिल्ली, एप्रैल 14। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार को नई दिल्ली के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों - भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबी एसएसएल), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसी ओएल) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। तीनों समितियों को विभाजित करना है। 2009 में न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित लोगों को निर्वासित किए जाने तक हिरासत में रखने के लिए हिरासत केंद्रों को अधिसूचित किया था।

मंत्रालय की एक और महत्वपूर्ण पहल है। काफी समय से तीनों समितियों के लिए अलग कार्यालय

समितियों के गठन को मंजूरी दी है। ये समितियाँ निर्यात, जैविक उत्पाद और बीज के क्षेत्र में काम

एनसीईएल के लिए निर्धारित गतिविधियों में रुचि रखने वाली सभी स्तरों की सहकारी समितियां इसकी सदस्यता के लिए पात्र हैं। ये तीनों समितियाँ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े लोगों का विकास सुनिश्चित करेंगी और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसएस) के माध्यम से किसानों से कृषि उपज और बीज खरीदेंगी। इससे पीएसएस और मजबूत होंगे क्योंकि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही समितियाँ यह भी सुनिश्चित करेंगी कि नेट सरप्लस यानी शुद्ध अधिशेष पर मुनाफा सीधे किसानों के खातों में पहुंचे।



भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की तीन बहुराज्यीय सहकारी

संपादकीय

सियायत का चेहरा जरदारी

आसिफ अली जरदारी करप्शन के आरोपों के सिलसिले में 11 साल जेल में रहे। पर, किस्मत का खेल देखिए कि अब वह दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। यही पाकिस्तान की राजनीति के स्याह चेहरे का सच है। पिछले तीन दशकों से, वे जेल और सत्ता के नजदीक रहे हैं। उन्हें संभवतः पाकिस्तान का सबसे बदनाम राजनेता माना जा सकता है, जो सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब रहा। व्हीलिंग और डीलिंग में माहिर रहे हैं जरदारी। वो 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद देश की राजनीति में आए थे। उसके बाद जरदारी अपने देश के राष्ट्रपति बन गए। बेशक, जरदारी से बेहतर सत्ता की राजनीति कोई नहीं कर सकता। एक दशक से अधिक समय तक जेल में रहने और लगातार विवादों में घिरे रहने के बाद, वह पाकिस्तानी राजनीति में अछूत से लेकर निर्बिवाद किंगमेकर बन गए। जरदारी एक चतुर और चालाक राजनीतिज्ञ साबित हुए हैं। उन्होंने दिसंबर 2007 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) नेतृत्व की कमान संभाली। उन्होंने 2008 के संसदीय चुनावों में पीपीपी को जीत दिलाई और सैन्य नेता जनरल परवेज मुशर्रफ को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। [कअमतउजपेमउमदज बेनजीर भुट्टो के पहले कार्यकाल के दौरान, जरदारी पर संपति हड़पने के लिए अपनी पत्नी के पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जरदारी ने हर सरकारी परियोजना पर कमीशन लिया और उन्हें मिस्टर टेन परसेंट का लेबल दिया। उन्हें अपनी पत्नी की पहली सरकार के पतन के लिए भी दोषी ठहराया गया। उन्हें पहली बार 1990 में गिरफ्तार किया गया। जरदारी ने ऐसे समय में राजनीतिक मैदान में उतरने का फैसला किया, जब सब कुछ उनके खिलाफ होता दिख रहा था। उन्होंने 1990 में अपने गृह नगर सिंध के नवाबशाह से नेशनल असेंबली सीट के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया था। कुछ हफ्ते बाद, उन्हें कई आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। वह चुनाव भी हार गए, लेकिन वे 1993 में नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। जब उनकी बेगम बेजत्री भुट्टो प्रधानमंत्री थीं, तब जरदारी पर्दे के पीछे से खेल खेलते थे और उन्होंने खुद को देश का सुपु्र प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर लिया था। जरदारी ने 200 से अधिक आरोपों में विशेष अदालतों में मुकदमे का सामना किया,जिसमें फिरोती के लिए अपहरण से लेकर बैंकों को धोखा देने से लेकर राजनीतिक विरोधियों की हत्या की साजिश रचने तक के केस शामिल थे। लेकिन उन पर लगे कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। 1992 में जमानत पर रिहा होने के बाद जरदारी का सितारा फिर से चमक उठा। यह पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक अविश्वसनीय क्षण था, जब जरदारी को जेल से रिहा किया गया और 1993 में नवाज शरीफ की पहली संघीय सरकार को हटाने के बाद बनी अंतरिम सरकार में उन्होंने संघीय मंत्री के रूप में शपथ ली। विडंबना यह है कि शपथ राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने दिलाई। उन्होंने ही जरदारी को जेल भेजने का रास्ता साफ किया था। दरअसल 1993 के चुनावों में पीपीपी की जीत के बाद, जरदारी उन सभी विवादों के साथ सत्ता में वापस आ गए, जिनके चलते बेनजीर भुट्टो सरकार गिरी थी। अब संघीय मंत्री जरदारी पर एक बार फिर भ्रष्टाचार और राजनीतिक हेराफेरी के आरोप लगने लगे। हालाँकि जरदारी को अतीत में कभी भी निर्णायक रूप से दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन पाकिस्तानी अवागम को जन्मत की हकीकत पता है। उनकी बहनों सहित उनके परिवार के कुछ सदस्य भी भ्रष्टाचार में कथित रूप से अकंट डूबे हुए थे। इमरान खान के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद लग रहा था कि अब आसिफ अली जरदारी की पारी का अंत हो गया। पर, आपको याद होगा कि जरदारी की पार्टी ने अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से इमरान खान की सरकार को हटाने के लिए मुस्लिम लीग (नवाज) और अन्य विपक्षी दलों के साथ हाथ मिला लिया था। तब इमरान खान की सरकार गिर गई थी और उसके बाद देश में गठबंधन सरकार बनी। जिसके प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बने और विदेश मंत्री जरदारी के पुत्र बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर जरदारी की भारत को लेकर रही सोच की बात करें तो वे कम से कम अपने ससुर जल्दिकार अली भुट्टो की तरह भारत विरोधी कभी नहीं लगे। वे कभी भारत नहीं आए हैं। उनकी अजमेर में गरीब नवाज की चौखट पर हाजिरी देने की ख्वाहिश थी। सन 2008 में पूरी होते–होते रह गई थी। तब जरदारी भारत आने वाले थे। पर वे चाहकर भी भारत नहीं आ पाए। उनका इरादा यही था कि दिल्ली आएंगे तो अजमेर में ख्वाजा मुहंमउद्दीन खिरती की मजार पर चादर तो चढ़ा ही लेंगे। दरअसल तब उन्हें राजधानी में एक अंग्रेजी अखबार की तरफ से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दावत दी गई थी। पर अफसोस कि तब भारत–पाकिस्तान के संबंधों में मौजूदा गर्मजोशी नहीं थी। तनाव को साफतौर पर महसूस किया जा सकता था। जाहिर है,जरदारी भारत नहीं आ पाए थे। जरदारी को इस बात जानकारी होगी ही कि उनके ससुराल का भारत के दो शहरों क्रमशः जूनागढ़ और मुम्बई से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। जब जरदारी की पत्नी बेनजीर भुट्टो की निर्म्म हत्या हुई थी तब जूनागढ़ में भी शोक की लहर दौड़ गई थी। यहां के वांशिदें बेनजीर भुट्टो को कहीं न कहीं अपना ही मानते थे।

महिला–संचालित विकास भारत की प्रगति के लिए उत्प्रेरक होगा

आसिफ दुनिया भर में, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक—आर्थिक प्रगति में महिलाओं की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। भारत में, महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर, भारत की प्रगति के प्रमुख स्तंभ के रूप में, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार के मजबूत फोकस के साथ एक आदर्श बदलाव आया है। यह हाल की कई नीतियों में स्पष्ट है जिसके कारण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है। महिला आश्चन विधेयक का पारित होना, जो महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक बड़ी आवाज देगा, एक परिवर्तनकारी कदम है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्वला योजना और पीएम मुद्रा

योजना जैसी कई योजनाओं और पहलों के बाद आया है, जो सभी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर लक्षित हैं। इस तरह की पहलों से जमीनी स्तर पर प्रभावशाली परिणाम मिले हैं और यह लैंगिक सशक्तिकरण में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। महिला श्रम बल भागीदारी दर में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है और अब यह 37 प्रतिशत है। मुद्रा योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आसान ऋण में मिल रहा है। महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन में काफी सुधार हुआ है और पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को 7.68 ट्रिलियन रुपये का ऋण मिला है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) के तहत, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते

आदित्य भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ये कानून किस हद तक प्रतिशोधात्मक न्याय के औपनिवेशिक मॉडल को पार करने और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांत को अपनाने में सक्षम हैं? पुनर्स्थापनात्मक न्याय अपराध करने से पहले मौजूद यथार्थिति को बहाल करने के उद्देश्य से अपराधी और पीड़ित के बीच संघर्ष को हल करने के लिए पुनर्स्थापनात्मक न्याय अपराध करने से पहले मौजूद यथार्थिति को बहाल करने के उद्देश्य से अपराधी और पीड़ित के बीच संघर्ष को हल करने का एक तंत्र है। न्याय वितरण के इस वैकल्पिक रूप के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि यह अपराधियों के अधिकारों के प्रति अधिाक संवेदनशीलता की मांग करता है। लेकिन पुनर्स्थापनात्मक न्यायरू विचार, मूल्य और बहस में, गैरी जॉनस्टोन पीड़ित और अपराधी के बीच समुदाय और पुलिस द्वारा की गई सीधी बैठकों के अनुभवजन्य साक्ष्य

गांधी के चरखे से मोदी की चिप तक

ललित भारत की उभरती भूमिका का परिचय से पूर्व की ओर विस्तार है। महात्मा गांधी के चरखे ने भारत की स्वतंत्रता क्रांति का इतिहास रचा, जिससे राजनीतिक मुक्ति हुई। यह न केवल स्वतंत्र भारत का प्रतीक था, बल्कि एक आत्मनिर्भर, सामाजिक—आर्थिक रूप से विकसित भारत की आशा भी थी, जिसने भारत के स्वदेशी, खादी उद्योग के प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक को जन्म दिया। 1918 में साबरमती आश्रम में खादी के जन्म ने 1924 में एक संस्थागत आकार लिया जब अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक 100 साल बाद, विकसित भारत /2047 का आत्मनिर्भरता का संस्करण एक अलग बदलाव के साथ आया है। हाथ से चलने वाले चरखे की जगह हाईटेक चिप ने ले ली है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के ढोलेरा और साणंद में और असम के मोरीगांव में तीन सेमीकंडक्टर संयंत्रों का शिलान्यास समारोह इस महत्वपूर्ण वैश्विक संपत्ति में भारत की उभरती भूमिका का पश्चिम से

देश अपने पहले प्रधान मंत्री का क्या ऋणी

विनोद भेरे जैसे पुराने समय के लोगों के लिए दुनिया उलट—पुलट हो गई है। भेरे बचपन और किशोरा वस्था में जवाहरलाल अनंत प्रशंसा के पात्र थे। चाचा नेहरू जहां भी जाते थे अपने लंबे कोट और लाल गुलाब से बच्चों की भीड़ को आकर्षित कर लेते थे। जिन सड़कों से वह गुजरा, लोग कतारबद्ध खड़े थे। उनमें, देश और उसके लोगों के प्रति उनके प्रेम, उनकी विद्वता, उनकी उच्च बुद्धि और उनकी सत्यनिष्ठा पर पूर्ण आस्था और विश्वास था। 1962 में चीन के साथ विनाशकारी युद्ध और 1964 में उनकी मृत्यु के बाद प्रशंसा भंग हो गई। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में यह हमारे हमवतन लोगों के एक वर्ग के बीच तीव्र नफरत में बदल गया है। उन पर आरोप तो खूब लग रहे हैं, मुख्य

आरोप यह है कि उन्होंने एक ऐसे राजवंश की स्थापना की जिसने भारत को बर्बाद कर दिया। क्या वह? जनवरी 1964 में उड़ीसा के गवर्नर के आधिकारिक निवास में नेहरू को आंशिक स्ट्रोक होने के बाद, भारत के भीतर और बाहर, हर किसी के मन में यह सवाल था, प्नेहरू के बाद, कौन? मुझे कई अखबारों के लेख याद आते हैं जिनमें अटकलें लगाई गई थीं कि नेहरू का उत्तराधिाकारी कौन हो सकता है। न केवल भारतीय अखबारों ने, बल्कि द टाइम्स ऑफ़ लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स और ऐसा कभी नहीं कहा गया कि नेहरू ने देश पर अपना उत्तराधिकारी थोपने का फैसला किया है। 1960 में प्रसिद्ध स्तंभकार फ्रैंक मोरेस ने लिखा, 'नेहरू द्वारा अपना खुद का राजवंश बनाने का प्रयास करने का कोई सवाल ही

नहीं हैय यह उनके चरित्र और करियर के साथ असंगत होगा।' उनकी मृत्यु के बाद, एक अन्यथा कटु आलोचक डी एफ काराका ने उनके इस संकल्प को सलाम किया कि ष्चपने उत्तराधिकारी के संबंध में किसी भी प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाएगा। यह उन लोगों का विशेषाधिकार था जो पीछे रह गए थे। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं थी। उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री मुद्दुभाषी और विनग्न थे, फिर भी अंदर से स्टील के बने थे। लेकिन उनके शीघ्र निधन से भारत का इतिहास अलग होना। यह भी कहा जाता है कि फेबियन समाजवाद के प्रति नेहरू का जुनून और सोवियत शैली की केंद्रीकृत योजना की प्रशंसा भारत को पीछे ले गई और इसके तीव्र विकास के रास्ते में आ गई। यह उस समय प्रचलित आर्थिक

वाले विकास को गति देने के लिए इसे और तेज किया जा सकता है। सबसे पहले, कई कंपनियों ने कार्यस्थल में लिंग—उत्तरदायी नीतियां शुरू की हैं। लक्षित भर्ती, अचेतन लिंग पूर्वाग्रह पर प्रशिक्षण आयोजित करना, सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए संवेदनशीलता और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के विभिन्न चरणों के माध्यम से महिलाओं को अधिक समर्थन महिलाओं को कार्यस्थल के भीतर रहने और बढ़ने में सक्षम बनाएगा। खुलासों पर उन्नत रिपोर्टिंग और विविधता सूचकांक तैयार करने से काम के लचीलेपन, बच्चों की देखभाल और छुट्टी से संबंधित लक्षित और साक्ष्य—आधारित हस्तक्षेप बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा, कई कंपनियाँ उन व्यवसायों या कार्यों के लिए महिलाओं को कुशल बनाने पर ६

साथ पारित किए गए थे। विधेयकों की समीक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति को दिए गए समय की कमी और उन पर चर्चा की कमी इस दवे पर प्रासंगिक सवाल उठाती है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को उपनिवेशवाद से मुक्त कर दिया गया है। कई देशों में, आपराधिक न्याय प्रणाली को उपनिवेश से मुक्त करने की खोज ने उन्हें अपराधों से निपटने के स्वदेशी तरीकों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया है। कई पूर्ववर्ती उपनिवेशों में आपराधिाक कानूनों का संहिताकरण औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ बढ़ते विद्रोह की पृष्ठभूमि में किया गया था। भारत में, भारतीय दंड संहिता का संहिताकरण 1837 में पूरा हो गया था। हालाँकि, ताज के खिलाफ असहमति की आवाजों को रोकने के लिए इसे अंततः 1860 में अधिनियमित किया गया था। आईपीसी की धारा 124ए जैसे प्राक्धान, जो सरकार के

चुआंग या इन्फोटेक इनोवेशन प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में सरकारों की भूमिका को दर्शाता है। यह अपरिहार्य है क्योंकि कॉर्पोरेट डिग्गज लम्बे हो रहे हैं और चिप प्रौद्योगिकी नैनो स्तर पर प्रतिस्पर्धी रूप से छोटी होती जा रही है। आइए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाने वाले दो हासिया उदाहरण लें, जबकि टीएसएमसी, सैमसंग और इंटेल का नामांकित कानून निष्प के आकार को छोटा कर रहा है और विनिर्माण उद्योग के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को वर्चस्व बनाए रखने के लिए सरकारी नीतियों को उत्त्पेरित कर रहा है। चिप वॉर्स चिप तकनीक युग की भू—राजनीतिक अंतर्धाराओं को प्रदर्शित करने के लिए ताइवान, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया और चीन के आंतरिक समायोजन का पता लगाता है। अमेरिका का ब्म्बै अधिनियम, दुनिया के सबसे उन्नत चिप निर्माता उैड६ और अन्य उत्पादकों और विश्वविद्यालयों के साथ ताइवान का ऐतिहासिक और निरंतर जुड़ाव और चीन का शिन

और सामाजिक परिस्थितियों की गलत समझ पर आधारित है। 1944—45 में जेआरडी टाटा, जीडी बिड़ला, अर्दशिर दलाल और जॉन मथाई जैसे व्यापारिक नेताओं और टेक्नोक्रेट्स द्वारा तैयार की गई बॉम्बे योजना में आर्थिक मोर्चे पर त्वरित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राज्य की भागीदारी और केंद्रीय योजना के महत्व पर जोर दिया गया था। बॉम्बे योजना पंचवर्षीय योजनाओं की अग्रदूत थी। इसमें 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पांच—पांच वर्षों के तीन खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें कृषि प्रमुख से उद्योग की ओर संक्रमण, बुनियादी उद्योग की परिकल्पना की गई। बुनियादी और भारी उद्योग सरकारी क्षेत्र में आ जाएंगे, जबकि उपभोक्ता उद्योग



प्रति घृणा या अवमानना या असंतोष की किसी भी अभिव्यक्ति को दंडित करते हैं, इसका प्रमाण हैं। गौरतलब है कि धारा 124ए को बीएनएस में धारा 150 के रूप में पुनर्गठित किया गया है। 2023 में अम्बेडकर जयंती के व्याख्यान में बोलते हुए, न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने संरचनात्मक भेदभाव के बारे में बात की, जो हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए का दुर्गम बनाता है। इस

कुछ जापानी खिलाड़ियों ने भी अपने एनवीडिया मोमेंट का अनुभव किया, जो चिप बनाने के उपकरण में माहिर है, मित्सुबिशी, डिग्गज लम्बे हो रहे हैं और चिप प्रौद्योगिकी नैनो स्तर पर प्रतिस्पर्धी रूप से छोटी होती जा रही है। आइए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाने वाले दो हासिया उदाहरण लें, जबकि टीएसएमसी, सैमसंग और इंटेल का नामांकित कानून निष्प के आकार को छोटा कर रहा है और विनिर्माण उद्योग के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को वर्चस्व बना दिया है। एनवीडिया का मूल्यांकन, जो हाल ही में +2.4 ट्रिलियन तक बढ़ गया है, जल्द ही जगह दूसरे स्थान पर आ सकता है। अपने प्रमुख नेटवर्क किट और सॉफ्टवेयर बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक एआई चिप बाजार के 80 प्रतिशत से अधिक को नियंत्रित करते हुए, एनवीडिया का एक बड़े धमाके के साथ आगमन डीए—टेक का महत्वपूर्ण क्षण है।

निजी उद्यम के लिए छोड़ दिए जाएंगे। नींव नेहरू के समय में रखी गई थी और इमारत का निर्माण, धैर्यपूर्वक और पीड़ा से, प्रगति और गिरावट के दौर के साथ, आज तक किया गया, जब हम आश्चर्य हो सकते हैं कि हम कुछ वर्षों में अनिवार्य रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। नेहरू लोकतंत्र में दृढ़तापूर्वक और अटल विश्वास रखते थे। मैक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पाज, जो कुछ वर्षों तक भारत में उस देश के राजदूत थे, ने 1966 में कहा था, 'ह्र्स सदी के अंधकारा राजनीतिक नेताओं के विपरीत, नेहरू को विश्वास नहीं था कि इतिहास की कुंजी उनके हाथों में है। क्योंकि इसने न तो अपने देश और न ही दुनिया को खून से दामा। यदि भारत पाकिस्तान और 20वीं सदी के कई अन्य नव स्वतंत्र

तरह के संरचनात्मक असंतुलन अन्याय की गलत समझ पर कानूनों को आधारित करने का परिणाम हैं। इससे हिंसा और असमानता को बढ़ावा मिला है. नए कानूनी कोड को पदानुक्रमित मॉडल के व्याख्यान में बोलते हुए, न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने संरचनात्मक आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। पुनर्स्थापनात्मक न्याय को परिवर्तनकारी न्याय की ओर ले जाना चाहिए।

गई।आरआईएससी—वी और शक्ति जैसी पिछली परियोजनाएं केवल सतही तौर पर काम कर रही हैं, जिनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। मोदी का आईएसएम कई मायनों में गेम—चेंजर साबित होने वाला है। फ़ैबलेस डिजाइन में भारत की बंग फाइव चिप उपकरण निर्माताओं—टोक्यो इलेक्ट्रॉन, एडवाटेस्ट, डिस्को, लेजरटेक और स्क्रीन होल्डिंग्स—ने एक वर्ष में अपनी बाजार पूंजी दोगुनी कर दी। छोटे आकार (2 नैनोमीटर तक) में चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन और एआई और क्रिप्टो जैसी परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के उदभव ने सेमीकंडक्टर वर्चस्व की दौड़ को पहले की तुलना में अधिक तीव्र बना दिया है। भारत के पास उपभोक्ता के बजाय सक्रिय उत्पादक बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत की विरासत फ़ैब (चिप निर्माण सुविधा), चंडीगढ़ में 1983 में स्थापित सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स, इसकी 2024 प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए अनुसंधान क्षमता निर्माण के लिए प्रस्तावित भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की सही पहचान की

देशों की राह पर नहीं चला है और मतपेटी के माध्यम से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा में दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, तो इसका श्रेय पूरी तरह से नेहरू को जाता है। जैसा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2014 में 10वें नेहरू मेमोरियल व्याख्यान में कहा था, 'स्वतंत्रता के समय भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना उपनिवेशवाद की लंबी अवधि से उभरने वाले नए राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालाँकि एक नए स्वतंत्र राष्ट्र में संसदीय लोकतंत्र को बड़ा जोखिम माना जाता था, लेकिन नेहरू ने इस प्रक्रिया को सफल बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उनकी दूरवृष्टि ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सीमित प्रतिनिधि सरकार को भारत के नागरिकों के लिए अनुकूल एक जीवंत और शक्तिशाली संस्थागत ढांचे में बदल दिया।

बेटी को गरियाने से कुपित छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट पीट कर मार डाला



हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) माधौगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरसठ कस्बे के मोहल्ला गांधीनगर में मामूली विवाद में छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई को लाठी से पीट दिया। घटना में बड़े भाई की मौत हो गई। मृतक की पत्नी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। कुरसठ कस्बे के मोहल्ला गांधी

नगर निवासी जयराम (45) राज मिस्त्री था। बुधवार रात लगभग 8 बजे जयराम शराब पीकर घर आया था। इसी दौरान उसने अपने छोटे भाई रामखेलावन की बेटी को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस पर रामखेलावन ने जयराम से आपत्ति जताई तो जयराम ने उसे भी गालियां देना शुरू कर दीं। इस पर गुस्साए

डीएम की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न 'शांतिपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाये होली पर्व-डीएम'

'ब्यूरो रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव 'शाहजहांपुर' जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में होली पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान

कार्य को जल्द पूर्ण कर लिया जाए। आबकारी अधिकारी को दिनांक 24-25 मार्च को पूर्व की भांति शराब की दुकाने बन्द रखने हेतु निर्देश दिये। डीपीआरओ को ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई का समुचित प्रबन्ध

कहा कि जुलूस में चलने के दौरान बिजली के खंभों तथा ट्रांसफार्मरों से दूरी बनाकर चलें जिससे कि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने सभी को आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आगामी पर्वों को मनाए जाने हेतु अपील की।

पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने कहा कि होली रंगों का पर्व है। इसे शांतिपूर्ण ढंग से आपसी भाईचारे के साथ मनाये। उन्होंने सुरक्षा सम्बन्धित जानकारी देते हुये बताया कि होली पर्व के दृष्टिगत जनपद में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा। होली पर्व पर निकाले जाने वाले जुलूस हेतु सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किये गये हैं। जुलूस की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में छतों पर ईंट, पत्थर, लोहे की रॉड आदि घातक वस्तुओं का एकत्रीकरण न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने छतों पर झ्रोन के माध्यम से निगरानी करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुये कहा कि आपसी मेल जोल के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाए तथा कोई भी ऐसी गतिविधि न करें जिससे माहौल खराब हो। बेहतर कानून व्यवस्था के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा सभी बिंदुओं पर विचारोपरान्त समुचित प्रबन्ध किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण जुलूस के दौरान निरन्तर सीसीटीवी कैमरों द्वारा कड़ी निगरानी की जायेगी। किसी भी प्रकार में महोल को खराब करने प्रयास न करें। यदि ऐसा करते कड़ई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

बैठक के दौरान नगर आयुक्त कामता प्रसाद, डीएफओ प्रखर गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी विठ्ठल सुरेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार, सीओ वीएस वीर सिंह, सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी सहित गणमान्य नागरिक एवं सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।



जिलाधिकारी ने होली के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से निकाले जाने वाले लाट साहब के जुलूसों का प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य नागरिकों, पुलिस अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होली को सकुशल संपन्न कराने के विषय में चर्चा की। बैठक में मौजूद गणमान्य नागरिकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों को जिलाधिकारी के साथ साझा किया। उन्होंने साफ-सफाई, बिजली, पानी तथा छुट्टा पशुओं आदि से सम्बन्धित समस्याओं को बताया। जिसका निस्तारण कराने हेतु जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जुलूस मार्ग में पड़ने वाले लटकते हुए ढीले तारों को तत्काल प्रभाव से ठीक कराया जाए, साथ ही उन्होंने खुले हुए ट्रांसफार्मरों को भी ढकने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जुलूस मार्ग में पड़ने वाले गड्ढों तथा अवरोधों को जल्द ठीक किया जाए। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि नगर क्षेत्र में बैरिकेडिंग के

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीएसए आफिस में हमारा आंगन हमारे बच्चे समारोह का हुआ आयोजन

सुलतानपुर। नगर में बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय के प्रांगण में आज उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग द्वारा 'एटम्व कार्यक्रम का आयोजन

ने सीडीओ से आईएसए बनने का सूत्र वाक्य पाते हुए गुरु के रूप में अभिवादन किया। कार्यक्रम के अंत में प्रशस्ति पत्र देकर बच्चों का हार्दिक बधाया गया। हमारे आंगन हमारे बच्चे समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में प्रज्वलित करते हुए बेसिक शिक्षा कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता से संबंधित बैनर और पोस्टर लगाए गए। इस दौरान यहां मौजूद लोगों को अवगत कराया गया कि किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़कर और सही उम्मीदवार

किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीडीओ अंकुर कौशिक शामिल हुए। उत्तर प्रदेश निर्वाचन विभाग के निर्देश पर आयोजित इस निपुण भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नन्हे मुन्हे बच्चे मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए। कुछ बच्चों

का चयन करते हुए हम राष्ट्र नवनिर्माण की दिशा में सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ पेंटिंग एवं प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्हे बच्चों ने मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक से मेधावी बनने और इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बारे में भी जानकारी हासिल की। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी की मौजूदगी में हौसला बढ़ाते हुए बच्चों ने अपने लक्ष्य से भी शिक्षकों को अवगत कराया। लगभग सभी विकासखंड में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए और शिक्षकों ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया। जिला विद्यालय निरीक्षक संदीप यादव, जिला समन्वयक श्याम यादव, अपेक्षा त्रिपाठी, धर्मेश कुमार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि लोग मौजूद रहे।



विद्यालय में तोड़फोड़ कर किया चोरी का प्रयास



ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर सिकरारा थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बयुआवर में बुधवार की रात अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ कर चोरी करने का प्रयास किया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा गुरुवार को थाने पर तहरीर देकर कारवाई की मांग की गई। गुरुवार को शिक्षण कार्य हेतु निर्धारित समय पर विद्यालय के शिक्षक

पहुंचे तो देखा कि विद्यालय की चहारदीवारी पर लगे सीसे को तोड़कर अंदर आकर तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास किया। अराजक तत्वों द्वारा विद्यालय परिसर में शराब पीकर दारू बोतल भी फोड़कर उधर उधर फेका गया है। शिक्षकों ने थाना पर तहरीर देकर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। जिससे विद्यालय में रखे सामानों की सुरक्षा हो सके।

उपजिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक



'ब्यूरो रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव 'पाली-(हरदोई)' तहसील शाहाबाद में उपजिलाधिकारी पूनम भास्कर ने सामान्य निर्वाचन 2024, जिससे माहौल खराब हो। बेहतर कानून व्यवस्था के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा सभी बिंदुओं पर विचारोपरान्त समुचित प्रबन्ध किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण जुलूस के दौरान निरन्तर सीसीटीवी कैमरों द्वारा कड़ी निगरानी की जायेगी। किसी भी प्रकार में महोल को खराब करने प्रयास न करें। यदि ऐसा करते कड़ई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

'लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक'



'ब्यूरो रिपोर्ट-जनार्दन श्रीवास्तव 'शाहजहांपुर' लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन अधिकारीधजिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ही बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी की मौजूदगी में हौसला बढ़ाते हुए बच्चों ने अपने लक्ष्य से भी शिक्षकों को अवगत कराया। लगभग सभी विकासखंड में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए और शिक्षकों ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया। जिला विद्यालय निरीक्षक संदीप यादव, जिला समन्वयक श्याम यादव, अपेक्षा त्रिपाठी, धर्मेश कुमार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि लोग मौजूद रहे।

प्रतिशत वाले बूथों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराने की प्रगति, तथा रमजान के पर्व पर जुमा के नमाजों हेतु सुरक्षा व्यवस्था ला एंड आर्डर, आईजीआरएस तथा समाधान दिवस के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु समीक्षा करके निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में क्षेत्राधिकारी शाहाबाद अनुज कुमार मिश्रा, तहसीलदार शाहाबाद नरेन्द्र कुमार पर साइनऐज, शौचालय, विद्युत, दिव्यांगों के लिए रैंप, आदि तथा क्रिटिकल तथा बल्नरेबल बूथों पिछले लोकसभा में कम वोटिंग

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराने की प्रगति, तथा रमजान के पर्व पर जुमा के नमाजों हेतु सुरक्षा व्यवस्था ला एंड आर्डर, आईजीआरएस तथा समाधान दिवस के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु समीक्षा करके निर्देशित किया गया। समीक्षा बैठक में क्षेत्राधिकारी शाहाबाद अनुज कुमार मिश्रा, तहसीलदार शाहाबाद नरेन्द्र कुमार पर साइनऐज, शौचालय, विद्युत, दिव्यांगों के लिए रैंप, आदि तथा क्रिटिकल तथा बल्नरेबल बूथों पिछले लोकसभा में कम वोटिंग

में 1246206 पुरुष मतदाता, 1075739 महिला मतदाता, 158 तृतीय लिंग, कुल 2322102 मतदाता है। जनपद का ईपी रेशियो 61.90 तथा जेण्डर रेशियो 863 है। 18-19 वर्ष के 51264 मतदाता तथा 20-29 वर्ष के 438923 मतदाता है। 21096 85-प्लस मतदाता, 365 100-प्लस मतदाता है। दिव्यांग 20574 तथा सर्विस 1303 मतदाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, जिसका समस्त राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को पालन किया जाना अनिवार्य है। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

यायावरों ने भारतीय संस्कृति को करीब से समझा - डा. कायनात काजी अपने पूर्वजों की विरासत को सहेजना होगा- एस एम मासूमब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। देश प्रख्यात यात्रा लेखिका एवं ब्लॉगर डॉ. कायनात काजी ने कहा कि यात्रा मन से नकारात्मकता को निकालती है। यायावरों ने संस्कृति को इतिहासकारों की तुलना में ज्यादा ईमानदारी से लिखा है। देश की लोक संस्कृति और धरोहरों को जानने के लिए मैंने यात्राएं कीं। यायावरों ने भारतीय संस्कृति को करीब से समझा। भारतीय संस्कृति की विविधता ही इसकी खूबसूरती है। डॉ. कायनात ने ये बातें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कल्चरल क्लब एवं जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में कहीं। विश्वविद्यालय में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन एवं दस्तावेजीकरण विषय पर पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उन्होंने प्रतिभागियों को देश के विभिन्न भागों की लोक संस्कृति से परिचित कराया। कल्चरल मैपिंग के लिए टिप्स भी दिए। कायनात काजी भारत की पहली एकल महिला यात्री हैं जिन्होंने केवल चार वर्षों में दो लाख किलोमीटर



विरासत पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करना और सांस्कृतिक पहचान को कायम रखने की जिम्मेदारी युवाओं की है। उन्होंने कहा कि जौनपुर जनपद की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध रही है इसे सहेजना बहुत मुश्किल नहीं है। अपने पूर्वजों की विरासत को बस सहेजना होगा। उन्होंने जौनपुर के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में विस्तार से बताया। प्रो. वी डी शर्मा ने कहा कि हमें अपनी

ने कहा कि जिज्ञासा ही पथ प्रदर्शक होती है। जितना देश में भ्रमण करेंगे संस्कृति वो वास्तव में समझ पाएंगे। जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ मनोज मिश्र ने अतिथियों का स्वागत एवं संचालन कार्यक्रम संयोजक डॉ दिग्विजय सिंह राठौर, धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव डॉ सुनील कुमार ने किया। इस अवसर पर एस अवसर पर डॉ. अवध बिहारी सिंह, डॉ. चन्दन सिंह, डॉ. सुरेन्द्र यादव, सोनम विश्वकर्मा, अमित मिश्रा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे।

मेदांता हास्पिटल लखनऊ ने हासिल की सफल 200 किडनी ट्रांसप्लांट की उपलब्धि

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की घोषणा की है। हॉस्पिटल ने अबतक 200 किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए हैं। मेदांता अस्पताल ने अपनी इस उपलब्धि को उन सभी अंगदाताओं को समर्पित किया है, जिन्होंने अपने अंगदान से अपने परिवार के सदस्यों को नया जीवन प्रदान किया। हॉस्पिटल ने उन सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस सफलता में अपना अमूल्य योगदान दिया। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के किडनी ट्रांसप्लांट विभाग का नेतृत्व डॉ. आर.के. शर्मा और डॉ. राकेश कपूर करते हैं। दोनों डॉक्टरों के पास किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उनकी टीम में अनुभवी डॉक्टरों और नर्सों का एक समूह शामिल है जो मरीजों को उच्चतम स्तर का इलाज और देखभाल प्रदान करते हैं। मेदांता हॉस्पिटल में सबसे छोटे 9५ साल के बच्चे से लेकर ७६ वर्ष के वृद्ध पेशेंट में ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसमें अपने देश के आलावा सऊदी अरबिया और अमेरिका के मरीज भी

शामिल है। मेदांता हॉस्पिटल में समान ब्लड ग्रुप वाले कंपैटिबल और आसमान ब्लड ग्रुप वाली इम्पैटिबल ट्रांसप्लांट सफलता पूर्वक हुए हैं और यह ट्रांसप्लांट यहां की विशिष्ट टीम, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन (एचएलए) लैब के सामूहिक प्रयास से सफल हुए हैं। मेदांता हॉस्पिटल किडनी रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान



करता है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, और किडनी रोगों का प्रबंधन शामिल है। हॉस्पिटल में एक अत्याधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट है, जो मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान करती है। हॉस्पिटल में किडनी की अन्य बीमारियों जैसे किडनी में पथरी, पेशाब की नली में पथरी, प्रोस्टेट

के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉ. राकेश कपूर, मेडिकल डायरेक्टर, मेदांता हॉस्पिटल ने कहा, हम उन सभी लोगों को ंन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस उपलब्धि में अपना योगदान दिया है। हम किडनी रोगियों के लिए बेहतर उपचार विकल्पों को विकसित करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे।

जौनपुर लोकसभा सदर से सपा निर्विवाद चेहरे पर लगा सकती हैं दाव

ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। जौनपुर की दो लोकसभा सीटें सदर और मछली शहर के लिए आगामी दिनों में होने वाले चुनाव के लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन लोगों की निगाहें ज्यादातर सदर लोकसभा सीट पर टिकते को लेकर चाय पाय की दुकान हो रिक्शा वाले हो या नुककड़ शहर के मुख्या योगी आदित्यनाथ सिंह राजनीति चर्चा ही सुनने को मिल रही हैं। लोगों द्वारा विभिन्न पार्टियों को लेकर तमाम तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को उतारने जा रही है हालांकि बात करें भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ दल की पार्टी है जहां पिछले चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी तो इस बार पार्टी ने सबसे पहले अपना पता खोलते हुए महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री व कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि कृपा शंकर सिंह कुछ ही समय पहले कांग्रेस का दामन



छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को लेकर अपनी निष्ठा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जो बोलता है जौनपुर के रहने वाले हैं लेकिन काफी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हुए महाराष्ट्र में की राजनीति में संसद देह राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद वर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव ६ मदन मोहन मदनारी से अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे थे लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री व कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि कृपा शंकर सिंह कुछ ही समय पहले कांग्रेस का दामन

उतर सकता है हालांकि उनके समर्थकों द्वारा जगह-जगह होल्डिंग और बैनर लगाकर शहर में हलचल सी पैदा कर दी गई है।अन्य पार्टियों के लोगों की निगाहें अपने-अपने चहेते उम्मीदवारों पर टिकी हुई हैं। बात करें विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी की तो सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही निर्विवाद चेहरे पर ही लोकसभा सदर सीट पर दांव लगाने के पक्ष में बोल चुके हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लालचंद यादव लाले को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोकसभा जौनपुर की सीट पर टिकट लेने का ही मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। डेढ़ दर्जन से अधिक लोग लखनऊ सपा मुख्यालय के आसपास डेरा जमाए बैठे हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो सदर लोकसभा सीट में गिनती की ही नेता इस कड़ी में फिट बैठते हैं। जिसमें क्षेत्र की जनता में सपा के वरिष्ठ नेता लालचंद यादव लाले के नाम की हुंकार भरी जा रही है। क्योंकि लोगों के बीच लाले की छवि बेहद सरल मिलनसार सबके दुख सुख के साथी के रूप में जाने जाते हैं।

